



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1974/श्रावण 4, 1896

No. 322]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1974/SRAVANA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July 1974

S.O. 452(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Maharashtra is hereby published :—

ORDER NO. 17

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) we hereby determine, on the basis of the latest census figures and having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Maharashtra as forty-eight (48) of which three (3) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and three (3) seats for the Scheduled Tribes and the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as two

hundred and eighty-eight (288) of which seventeen (17) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and seventeen (17) seats for Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, Chairman.

TARUN KUMAR BASU, Member.

T. SWAMINATHAN, Member.

[No. 282/74(2)]

By order,

P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1974

का० आ० 452 (अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत दिया गया महाराष्ट्र राज्य के बारे में आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश संख्या 17

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में, हम, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तथा सविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 तथा 332 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये महाराष्ट्र राज्य को आवंटित किये जाने के लिये लोक सभा में स्थानों की संख्या के रूप में अड़तालीस (48) स्थान जिनमें से तीन (3) स्थान अनुसूचित जातियों के लिये तथा तीन (3) स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित होंगे तथा उक्त राज्य की विधान सभा के लिये समनुदेशित स्थानों की कुल संख्या के रूप में दो सौ अड़तालीस (288) स्थान, जिनमें से सत्रह (17) स्थान अनुसूचित जातियों के लिये और सत्रह (17) स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित होंगे, एतद्वारा अवधारित करते हैं।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष ।

तरुन कुमार बसु सदस्य ।

ति० स्वामिनाथन सदस्य ।

[स० 282/74 (2)]

आदेश से

पी० आई० जेकरा, सचिव ।